

(516)

राजस्थान सरकार
नगर विकास विभाग

क्रमांक: - प. 6118 नविआ/3/90

दिनांक- 23-4-2003

सचिव,
नगर विकास न्यायालय,
अजमेर ।

विषय:--अमझोला समिति की बैठक दिनांक 5-1-2002 एवं दिनांक
6-5-2002 में भूमि के बट्टे 15 प्रतिशत भूखंड आवंटन के
अनुमोदन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार स्पष्ट है कि न्याय न्यायिक समिति द्वारा निर्णित प्रस्तुत मामलों में से उन मामलों में 15 प्रतिशत विकसित भूखंडों का आवंटन आपके स्तर पर किया जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवम् वर्तमान में प्रचलित प्रभावी परिपत्रों/आदेशों से कवर होने वाले प्रकरणों में एतद्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति दी जाती है ।

साथ करते समय न्याय न्यायिक बात का विशेष ध्यान रहे कि जिन मामलों में दिनांक 21-9-99 से पूर्व 12 प्रतिशत विकसित भूखंडों सार्वजनिक/भू-स्वामी को उपलब्ध कराकर भूमि अवाप्ति की जा चुकी है, उन मामलों में 15 प्रतिशत विकसित भूमि का प्रावधान लागू नहीं होता है ऐसा कि विभाग के परिपत्र दिनांक 21-9-99 द्वारा स्पष्ट किया हुआ है ।

भवदीय,

उपशासन सचिव

(37)
(46)